हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 100 लखनऊ, मंगलवार 25 नवंबर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

सनातन के शिखर पर मोदी लहराएंगे भगवा ध्वज, इन 32 मिनट में होंगे सभी अनुष्ठान

एजेंसी

अयोध्या। रामनगरी मंगलवार को ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण का यह महापर्व परंपरा, आस्था और राष्ट्रभावना का अनोखा संगम बनेगा। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:30 बजे तक है। 32 मिनट का यह शुभ योग भगवान श्रीराम के जन्म नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त से मेल खाता है। ध्वजारोहण समारोह के लिए 21 नवंबर से चल रहे अनुष्ठानों की भी पूर्णाहुति मंगलवार को होगी। सुबह छह से 10 बजे तक अनुष्ठान होंगे। प्रधानमंत्री राम दरबार व गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर पूजन करेंगे। यहां से वह सप्तऋषि मंदिर और फिर माता अन्नपूर्णा मंदिर में प्रार्थना कर मुख्य समारोह में भाग लेंगे। चार से पांच मिनट के संक्षिप्त ध्वजारोहण अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री बटन दबाकर ध्वज फहराएंगे। सात हजार अतिथि समारोह के साक्षी बनेंगे, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, , धर्मगुरु, व्यापार जगत के प्रमुख नाम, दलित, वंचित, किन्नर और अघोरी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। ध्वजारोहण की इस ऐतिहासिक अवसर पर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक भव्य मंगल–स्वस्ति गान प्रस्तुत कर रहा है। यह एक दिव्य संगीतमय अर्पण है, जिसका उद्देश्य पूरे वातावरण को आध्यात्मिक आभा से आलोकित करना है। देशभर के प्रतिष्ठित कलाकार इस पावन क्षण पर अपने स्वरों से भजन प्रस्तुत करेंगे। श्री रामचरितमानस के चुनिंदा प्रसंगों का गायन करेंगे और विभिन्न संत–परंपराओं की ओर से रचित मंगलमय काव्यों का सामूहिक वाचन करेंगे। ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर ध्वजारोहण करने के साथ देश–दुनिया को राम मंदिर के

निर्माण की पूर्णता का संदेश देंगे। मंगलवार को चार घंटे का उनका अयोध्या प्रवास होगा। पीएम विशेष विमान से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर आएंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से रोड शो करते हुए राम मंदिर जाएंगे। पीएम के आगमन को देखते हुए एसपीजी ने सुरक्षा की कमान अपने हाथों में संभाली ली है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रामनगरी में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी मंगलवार को सुबह 9.30 बजे विशेष विमान से महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि व भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीएम एयरपोर्ट से हेलाकॉप्टर से साकेत कॉलेज परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर आएंगे। हेलीपैड से पीएम का काफिला रामपथ पर रोड शो करते हुए जगद्गुरु आदि शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करेगा। रोड शो के दौरान भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी रामपथ पर पीएम मोदी के रोड शो के दौरान भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी है। करीब एक किमी लंबे इस मार्ग के दोनों तरफ 12 स्थानों पर महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से पुष्प वर्षा के साथ उनकी अगवानी की जाएगी। साकेत कॉलेज के गेट पर वैदिक आचार्यों के नेतृत्व में बटुक शंख ध्वनि के साथ स्वस्तिवाचन करेंगे। सात स्थानों पर बनाए गए सांस्कृतिक मंचों पर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए लोक कलाकार संगीत की त्रिवेणी नृत्य, वादन और गायन प्रस्तुत करेंगे। सुबह 10 बजे राम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी और संघ प्रमुख राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत सुबह 10 बजे राम मंदिर पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी होंगी। पीएम मोदी सबसे पहले राम जन्मभूमि में सप्त ऋषि मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद शेषावतार मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे। दर्शन–पूजन और परिसर का भ्रमण करने के बाद ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में आठ हजार मेहमान शामिल होंगे। शुभ मुहूर्त में सुबह 11:58 से दोपहर एक बजे के मध्य पीएम राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। इसके बाद उनका संबोधन होगा। पीएम दोपहर 1:30 बजे राम मंदिर से वापस एयरपोर्ट जाएंगे। राम मंदिर के ध्वज दंड पर मढ़ा 21 किलो सोना ध्वजारोहण समारोह के लिए राम मंदिर को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे दंड पर सोना मढ़ा गया है। करीब 21 किग्रा सोना, इस दंड पर लग रहा है। इस काम को मुंबई से आए कारीगरों ने पूरा किया है। बता दें कि पांच अगस्त, 2020 को जिस भूमि तल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था, शिखर के नाभि दंड का निर्माण उसी स्थल पर किया गया है। यह भूमि पूजन भूमि की सतह से करीब 50 फीट नीचे किया गया था। वर्तमान में इसकी ऊंचाई शिखर तक है, जो कि सतह से 161 फीट ऊंचा है। इस तरह नाभि दंड की कुल ऊंचाई 211 फिट है। फिलहाल इस नाभि दंड की कुल लंबाई में भूमि तल से ऊपर दिखाई दे रहे दंड को स्वर्ण मंडित किया जा रहा है। इस नाभि दंड की नाप–जोख पहले हो गई थी। उसी नाप–जोख के अनुसार मुंबई के कारीगर यहां दंड का आवरण लेकर राम मंदिर में आए हैं और नाभि दंड पर स्वर्ण का आवरण चढ़ाया गया है। राम मंदिर के पश्चिम दिशा में इस नाभि दंड को देखा जा सकता है जिस पर आधे से अधिक लंबाई में स्वर्ण पत्तल चढ़ा दिया गया है। पीएम और संघ प्रमुख के लिए लगी तीन–तीन एंबुलेंस ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ चिकित्सकों की टीम तैनात की गई है। दोनों के काफिले में तीन–तीन एंबुलेंस में चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। सीएमओ डॉ. सुशील कुमार बानियान ने बताया कि ध्वजारोहण को लेकर समस्त तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रीराम अस्पताल में भी 40 बेड का वार्ड आरक्षित किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 60 बेड आरक्षित हैं। मेडिकल कॉलेज में सेफ हाउस बनाया गया है, जहां विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है।

सहारा समूह के निदेशकों की संपत्तियां तलाशेगा ईडी, कई अधिकारियों के पास मिली आय से अधिक की संपत्ति

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। सहारा इंडिया परिवार के पूर्व उप निदेशक ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना शिकंजा कस दिया है। एजेंसी ने श्रीवास्तव के साथ–साथ एक दर्जन से अधिक पूर्व और वर्तमान निदेशकों की चल–अचल संपत्तियों की तलाश और ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है। निवेशकों की जमापूंजी हड़पने के आरोप में इन पदाधिकारियों की संपत्तियों को जल्द ही जब्त किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, ईडी, कोलकाता की इन्वेस्टिगेशन विंग सहारा समूह की उन कंपनियों के पूर्व एवं वर्तमान निदेशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, जिन्होंने पोंजी स्कीम चलाकर निवेशकों से रकम जमा की। जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख कंपनियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और एक दर्जन से अधिक अन्य कंपनियां शामिल हैं, जिनके निदेशक बार–बार बदले गए थे। ईडी ने इस

साल अप्रैल में देश भर के 16 शहरों में इन कंपनियों की कुल 1538 करोड़ रुपये कीमत वाली 1073 एकड़ भूमि को पहले ही जब्त कर लिया था। इस कार्रवाई में लखनऊ, मुरादाबाद और ललितपुर की जमीनें भी शामिल थीं। लखनऊ में, ईडी ने घैला तहसील के अलू नगर डिगुरिया और बक्शी का तालाब तहसील के नरहरपुर गांव में खरीदी गईं 107 एकड़ भूमि जब्त की थी। ईडी को इन जमीनों पर बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी भी मिली है, जिसके बाद संबंधित उप निबंधक कार्यालयों को इन संपत्तियों की खरीद–फरोख्त पर रोक लगाने के लिए पत्र भेजा जाएगा। बेनामी संपत्तियां खरीदी गईं ईडी की जांच में सामने आया है कि इन कंपनियों में निवेशकों की गाढ़ी कमाई जमा कराने के बाद दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में इससे तमाम निदेशकों ने अपने नाम से बेनामी संपत्तियां खरीदीं। अब ईडी इन संपत्तियों को जब्त करने के साथ बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा।

तमिलनाडु बड़ा हादसा, दो बसों की टक्कर में आठ लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल

एजेंसी / चेन्नई। तमिलनाडु के दक्षिणी तेनकासी जिले में दो प्राइवेट बसों की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गयी और बच्चों समेत 30 से अधिक लोग घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में पांच महिलाएं शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय को मिली रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि हादसे में आठ लोगों की मौत हो गयी। यह हादसा कदयानल्लूर के पास इदैकल गांव में हुआ। बचाव दल को दुर्घटनाग्रस्त बसों में फंसे लोगों को निकालने के लिये कड़ी मशक्कत करनी पड़ी जो तेज रफ्तार की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना मिलने पर पुलिस, अग्निशमन और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोग भी राहत कार्य में लगे हुए थे।

युवक की हत्या, सीमेंट की बोरियों से बांधकर नाले में फेंका शव, दो दिन से लापता था

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ में निगोहां क्षेत्र के राधाकृष्ण खेड़ा गांव निवासी अमित कुमार की हत्या कर शव गौतमखेड़ा गांव स्थित बांक नाले में फेंक दिया गया। हत्यारों ने शव दो बोरियों से बांधकर नाले में फेंका। इनमें मौरंग भरी थी, ताकि शव न उतराए। एसीपी मोहनलालगंज विकास कुमार पांडेय के मुताबिक मजदूरी करने वाला अमित दो दिन से लापता थे। लोगों ने उन्हें आखिरी बार शुक्रवार को देखा था। परिजनों ने गुमशुदगी नहीं दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उधर, ग्रामीणों का कहना है कि अमित के गले पर कसाव के निशान मिले हैं।आशंका जताई जा रही है कि अमित की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को छिपाने के लिए नाले में फेंक दिया गया। एसीपी ने बताया कि ग्रामीणों ने शव उतराता देखकर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से शव को निकलवाया गया। इस दौरान पता चला कि शव के साथ रस्सी से मौरंग भरी दो बोरियां भी बांधी गई हैं। आशंका है कि हत्यारे नहीं चाहते थे कि अमित के शव की पहचान हो सके। हत्या के पीछे करीबियों की संलिप्तता का शक जताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी होने से शिनाख्त पुलिस ने काफी देर तक स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान कराने का प्रयास किया। प्रधान ने भी शव की तस्वीर ग्रामीणों को भेजी, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी करने के बाद शव की पहचान राधाकृष्ण खेड़ा गांव निवासी ईश्वरदीन के बेटे अमित के रूप में हुई। बड़े भाई बेचा और छोटे भाई प्रेम ने बताया कि अमित नशे का आदी था। वह अक्सर घर से लापता हो जाता था। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। जमीन विवाद की दिशा में छानबीन पुलिस सूत्रों का कहना है कि अमित का कुछ लोगों से जमीन का विवाद चल रहा था। मामले में कोर्ट में वाद भी दाखिल किया गया था। पुलिस जमीन विवाद की दिशा में छानबीन कर रही है। अमित के साथ काम करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। हत्या में एक से अधिक लोगों की भूमिका की बात सामने आई है। महिला की भी हत्या कर इसी नाले में फेंका था घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले एक महिला की भी हत्या कर बोरी में शव भरकर इसी नाले में फेंका गया था। शव पानी से बाहर न आए, इसके लिए बोरी में ईंट व पत्थर भरा गया था। अमित की हत्या भी इसी तरीके से की गई। पुलिस दोनों मामलों को जोड़कर देख रही है। इसके पहले बहन के प्रेम विवाह से नाराज युवक ने भी बहनोई की हत्या कर शव इसी नाले में फेंका था। थाना प्रभारी अनुज तिवारी ने बताया कि घटना की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने नाले के पास निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में कौन-सा वाद बनेगा सभी का प्रतिनिधि?

–एक दिसंबर को आएगा सुप्रीम फैसला

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामलों में अब एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि भगवान श्रीकृष्ण के समस्त भक्तों का प्रतिनिधि वाद कौन–सा होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए मूल वाद के वादकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रतिनिधिक क्षमता उसी वाद को मिलनी चाहिए, जो सबसे पहले दायर किया गया था। इसी विवाद पर सर्वोच्च अदालत एक दिसंबर को सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 में वाद संख्या–17 को यह मानकर प्रतिनिधिक दर्जा दिया था कि इसके वादकर्ता सभी कृष्ण भक्तों की ओर से मुकदमा चला सकते हैं। हालांकि मूल वाद संख्या–1 के वादकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनका वाद पहले दायर हुआ था और अन्य वाद इसी की नकल हैं। ऐसे में किसी भी प्रतिनिधिक वाद का आधार मूल वाद होना चाहिए, न कि बाद में दायर कोई याचिका। कोर्ट में आज क्या हुआ? जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया और कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत बहस जरूरी है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत को बताया कि वाद संख्या–1 को

हाईकोर्ट में लीड मामला घोषित किया गया था। ऐसे में यह स्वीकार्य नहीं है कि वाद संख्या–17 को सभी कृष्ण भक्तों का प्रतिनिधि माना जाए। दीवान ने यह भी आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं किया और अन्य समेकित वादों के पक्षकारों को नोटिस दिए बिना यह निर्णय ले लिया। हाईकोर्ट ने क्यों दिया था वाद–17 को प्रतिनिधिक दर्जा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वाद संख्या–17, जो श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से उनके नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से दायर किया गया था, उसे सीपीसी के आदेश–1 नियम–8 के तहत प्रतिनिधिक क्षमता दी जाती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि इस वाद में प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि माना जाएगा। इस आदेश के तहत 18 में से 15 वाद एक साथ जोड़े गए, जबकि तीन अलग सूचीबद्ध रहे। इसी आदेश को मूल वादकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वाद–17 के वादकर्ताओं ने क्या कहा? वाद संख्या–17 के वादकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुकृष्ण कुमार ने कहा कि जब सभी वाद एक ही उद्देश्य से लड़े जा रहे हैं, तो प्रतिनिधिक वाद को लेकर विवाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी वादकर्ताओं को जवाब देने का अवसर दिया था और प्रक्रिया का पालन किया गया है। उनके अनुसार, प्रतिनिधिक दर्जा देने का उद्देश्य मुकदमों की सुनवाई को सुव्यवस्थित करना है, न कि मूल वादकर्ताओं के अधिकार कम करना। एक दिसंबर को होगी बड़ी सुनवाई अब पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक दिसंबर को विस्तृत सुनवाई करेगा। अदालत यह तय करेगी कि 18 मामलों वाले इस संवेदनशील विवाद में किस वाद को सभी श्रीकृष्ण भक्तों का वैध प्रतिनिधि माना जाए। विवाद का यह पहलू महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रतिनिधिक वाद का निर्णय सीधे तौर पर अन्य सभी मामलों की दिशा तय करेगा। फिलहाल सभी वादों की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड और नए डीपीएसयू के बीच टकराव, आयुध कारखानों के निगमीकरण का विरोध

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डनेंस एम्प्लॉइज (यूएफओई) और पूर्ववर्ती ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) से बने सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के बीच एक नया टकराव शुरू हो गया है। वजह, कर्मचारियों के समावेश का विवादास्पद मुद्दा, निगमीकरण के पांच साल बाद भी नहीं सुलझ नहीं सका है। भारत सरकार ने 2021 में 41 आयुध कारखानों का निगमीकरण किया था। इन कारखानों को सात डीपीएसयू में पुनर्गठित किया गया। एआईडीईएफ और बीपीएमएस सहित कर्मचारी संघों ने इस निर्णय का विरोध किया। कर्मचारियों ने दिवंगत मनोहर परिकर सहित पूर्ववर्ती रक्षा मंत्रियों की इस प्रतिबद्धता का हवाला दिया कि आयुध कारखानों का निगमीकरण नहीं किया

जाएगा। इसके बावजूद निगमीकरण कर दिया गया। एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार के मुताबिक, यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय भी पहुच चुका है। न्यायालय ने निगमीकरण को एक नीतिगत निर्णय माना, लेकिन सरकार की लिखित प्रतिबद्धता–विशेषकर उसके हलफनामे के पैरा 55(क) और (ख)–पर जोर दिया कि कर्मचारी तब तक केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे, जब तक कि वे आमेलन का विकल्प न चुनें। रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) ने सात नए डीपीएसयू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को निगमों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए आमेलन पैकेज के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया। सचिव (रक्षा उत्पादन) ने 10 नवंबर को एक बैठक आयोजित की। सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों से इस बैठक में भाग लेने का आग्रह किया गया। श्यूएफओईश ने श्डीपीएसयूश् के साथ बैठकों को अस्वीकार कर दिया। 20 नवंबर को एक वर्चुअल बैठक में, यूएफओई ने सर्वसम्मति से नए डीपीएसयू के सीएमडी द्वारा आयोजित किसी भी बैठक में शामिल न होने का संकल्प लिया। वजह, 41 कारखानों के 80 प्रतिशत से अधिक रक्षा असैन्य कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहने के लिए पहले ही अग्रिम विकल्प प्रस्तुत कर दिए हैं। 863 आईओएफएस अधिकारियों ने भी इसी तरह के अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

भारत, कनाडा एफटीए वार्ता फिर शुरू करने पर सहमत : गोयल

एजेंसी

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इसका मकसद 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। गोयल ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि एफटीए या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) में कई रणनीतिक पहलू होते हैं और यह दोनों देशों के बीच विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों पक्षों के निवेशकों और कारोबारियों का विश्वास बढ़ेगा। मंत्री ने कहा, ''हम उच्च–महत्वाकांक्षी सीईपीए पर वार्ता शुरू करने और 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं और एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। गोयल ने कहा कि भारत

और कनाडा की ताकतें व्यवसायों एवं निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती हैं। मंत्री ने कहा, ''हम कनाडा से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कनाडा को बहुत कुछ दे सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और महत्वपूर्ण खनिजों की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में अपार संभावनाएं हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, खासकर यूरेनियम आपूर्ति के क्षेत्र में कनाडा के साथ हमारे सहयोग को लेकर अच्छी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, ''हम दोनों ओर अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता ला सकते हैं। कनाडा ने 2023 में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी थी। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के संभावित संबंध होने के कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को ''बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। मार्च 2022 में दोनों देशों ने एक अंतरिम समझौते के लिए वार्ता फिर से शुरू की थी।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 'साइलेंट हंटर' यानी एंटी–सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट 'माहे

एजेंसी

नयी दिल्ली। सोमवार को 'साइलेंट हंटर' यानी एंटी–सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट 'माहे' भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नौसेना का यह एंटी–सबमरीन जहाज गोपनीय मिशन, सतर्कता और अटूट संकल्प का प्रतीक है। नौसेना के मुताबिक 'माहे' को तटीय इलाकों में उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमताएं इसे एक शक्तिशाली व उथले पानी का बेहतरीन योद्धा बनाती हैं। यह जहाज पनडुब्बी रोधी जैसे बड़े व खतरनाक अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है।रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नौसेना के इस जहाज में इस्तेमाल की गई 80 प्रतिशत से अधिक सामग्री स्वदेशी है।

कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज, श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात –3.2 डिग्री रही

एजेंसी

जम्मू। मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान –3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में –4.0 डिग्री और गुलमर्ग में –1.9 डिग्री दर्ज किया गया। साउथ कश्मीर में भी ठंड और तेज हो गई।

संपादकीय

श्रम संहिताएं शोषण का नया औजार

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर चार श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। इनमें से मजदूरी संहिता 2019 में संसद ने पारित की थी। अन्य तीनों संहिताएं सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 में संसद में पारित की जा चुकी हैं। लेकिन इसके बाद इन्हें लागू करने पर कोई बात नहीं हुई, तो समझा गया कि इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2024 में मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी खत्म हो गया। फिर चुनाव में जीत कर नरेन्द्र मोदी ने तीसरा कार्यभार संभाला, उसके बाद भी इन श्रम संहिताओं पर कोई बात नहीं हुई। अब यकायक मोदी सरकार ने इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर सबको चौंका दिया। सरकार इस फैसले को कर्मचारियों और मजदूरों के हित में बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्आज, हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं। यह आजादी के बाद मजदूरों लिए सबसे बड़े और प्रगतिशील सुधारों में से एक है। यह हमारे कामगारों को बहुत ताकतवर बनाता है। इससे नियमों का पालन भी काफी आसान हो जाएगा और यह श्ईज ऑफ डूइंग बिजनेसश को बढ़ावा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने इन्हें आजमाए बिना ये तो कह दिया कि ये मजदूरों के सबसे प्रगतिशील सुधारों में से एक हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले कार्यकाल में इन सुधारों को लागू करने से उन्हें किसने रोका था और अब अचानक इन्हें लागू क्यों किया गया। ध्यान रहे कि जिस समय इन संहिताओं को पारित कराया गया, वह कोरोना महामारी का दौर था। जिसने नोटबंदी के बाद त्रस्त जनता की कमर बुरी तरह तोड़ दी थी। लाखों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए थे। तब नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लुभावना नारा दिया था। अभी श्रम संहिताओं को लागू करते वक्त फिर इसी आत्मनिर्भर भारत की बात ही कही जा रही है। मगर मजदूर संगठन अब भी यह नहीं मान रहे हैं कि इनसे मजदूरों का भला होगा। पांच साल पहले भी उन्होंने इसका विरोध किया था, और वे अब भी यही कह रहे हैं कि यह पूंजीपतियों के हितों को देखते हुए बनाए गए हैं।श्रम संहिता के खिलाफ इंटक, एटक, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एईडब्लूए, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी जैसे मजदूर संगठनों ने 26 नवंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन का +फैसला भी किया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्मजदूरों से जुड़े 29 मौजूदा कघनूनों को 4 कोड में री–पैकेज किया गया है। इसका किसी क्रांतिकारी सुधार के तौर पर प्रचार किया जा रहा है, जबकि इसके नियम अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुए हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, श्लेकिन क्या ये कोड भारत के मजदूरों की न्याय के लिए इन 5 जरूरी मांगों को हकघिकघ्त बना पाएंगे?देखना होगा कि मोदी सरकार इन सवालों के जवाब देती है या इन्हें अनदेखा कर देती है। वैसे सरकार का दावा है कि साल 2019 के वेज कोड से कामगारों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिल सकेगी और हर पांच साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जाएगी। लेकिन जिस देश में साल में कई बार महंगाई के झटके लगते हैं, वहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए पांच साल क्या ज्यादा लंबा वक्त नहीं है। सरकार का यह भी दावा है कि इससे सभी कामगारों को समय पर वेतन मिलने की गारंटी भी दी जाएगी और महिलाओं और पुरुषों को समान मेहनताना मिल सकेगा। एक छोटे से योगदान के बाद सभी कामगारों को ईएसआईसी के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और यह सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिहाज से काफी अहम होगा।अच्छी बात है कि इन संहिताओं में इस तरह के प्रावधान हैं, लेकिन महिलाओं को समान वेतन के साथ ही रात में काम के लिए बुलाने की भी छूट दी गई है। बेशक इसमें महिलाओं की सहमति जरूरी होगी, लेकिन इसके बावजूद महिला शोषण के खतरे बढ़ जाएंगे। नयी श्रम संहिता में श्रमिकों को हड़ताल की अनुमति नहीं है, चाहे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए, चाहे पगार कम कर दी जाए, वे अपने हक के लिए संगठित होकर खड़े नहीं हो पाएंगे। गौरतलब है कि भारत में मजदूर संगठनों ने लंबी लड़ाई के बाद कामगारों के हित में 44 कघनून बनवाए थे। जिनमें काम के निर्धारित घंटे, श्रम संगठन बनाना, श्रमिकों के हितों के लिए सामूहिक तौर पर सौदेबाजी कर पाने की क्षमता वगैरह शामिल थे। लेकिन मोदी सरकार में इन सब खत्म कर दिया गया है। अहम बात यह है कि संहिता और कघनून में फर्क होता है। कघनून में सजा का प्रावधान होता है, जबकि संहिता में कंपनीध्फैक्टरी मालिकों पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

राशिफल

मेष :– कोई छोटी बात भी परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता हेतु नये उत्साह का संचार होगा। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंध मधुरत होंगे।

वृषभ :– हर घटना से आपको सीख लेने की जरूरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्व जानकार लोगों से विचार–विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशाजनक विचारों को मन पर हावी न होने दें। नये व्यावसायिक यात्राओं का योग है।

मिथुन :– निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुंदर छबि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। घर में खुशहाली होगी।

कर्क :– भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं उत्पन्न होंगी। किसी कार्य को छोटा–बड़ा समझने के बजाए अपने कर्त्तव्यों का सही ढ़ंग से निर्वहन करें। वर्तमान कार्य से मन असंतुष्ट रहेगा। जरूरी कायरे में आलस्य का त्याग करें।

सिंह :– पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु चिंता उत्पन्न होगी। अपने स्वास्य के प्रति लापरवाही न बरतें एवं जीवन साथी के स्वास्य के प्रति भी ध्यान दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित साधन लिए मन प्रयत्नशील होगा।

कन्या :– परिवार की छोटी–छोटी बातों बाहरी लोगों से न कहें। भावना से उद्वेलित मन संबंधियों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

तुला :– समय के साथ समझौता करके चलने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र को ही अपनी पूजा समझें और स्वयं को उसी ओर केंद्रित करें। पत्नी के साथ मधुर वणी का प्रयोग करें। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी।

वृश्चिक :– स्वयं को सही दिशा और लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे।

धनु :– किसी भी प्रयास में आर्थिक अभाव अवरोधक होगा। साहस व बुद्दिमत्ता से पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

मकर :– बुद्धिमत्ता व परिश्रम का मिले–जुले संयोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताएं आंतरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी।

कुंभ :– शासन–सत्ता में व्यस्तता बढ़ेगी। मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु चिंतित होगा। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन चिंतित होगा।

मीन :– महत्वाकांक्षी अभिलाषाएं मन में असन्तिुष्ट पैदा करेंगी। तामसिक विचारों को मन से दूर ही रखें। विपरीतलिंगी संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अपेक्षित है।

जब कानून और समाज आमने-सामने खड़े हों

व्यक्ति की स्वतंत्रता, पारिवारिक मर्यादा और एक त्रासदी का गहन सामाजिक विश्लेषण

–डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत जैसे विशाल और विविध सामाजिक ढाँचे वाले राष्ट्र में व्यक्ति के अधिकार और समाज की सामूहिक मर्यादाएँ एक–दूसरे से लगातार टकराती रहती हैं। संविधान व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है, लेकिन सामाजिक परम्पराएँ यह स्वीकार नहीं कर पातीं कि कोई लड़की या लड़का परिवार की इच्छा और बिरादरी की मान्यताओं से अलग कोई जीवननिर्णय ले। यह संघर्ष नया नहीं है, लेकिन आज की जमीनी हकीकत में इसका तनाव कहीं अधिक विकराल रूप ले चुका है। हाल ही की एक त्रासदी में यही टकराव खुलकर सामने आया, जब एक युवती ने अपने ही गाँव के युवक से विवाह कर लियाकृऐसा विवाह जो पूरी तरह कानूनी था, लेकिन समाज की दृष्टि में सर्वथा अस्वीकार्य। सामाजिक विरोध, पंचायत की मनाही, परिवार की पीड़ा और प्रतिष्ठा के दबाव के बीच लड़की शहर चली गई थी, पर कुछ समय बाद वापस अपने ही पैतृक गाँव में बहू बनकर लौट आई। यही वापसी समाज को चुनौती की तरह दिखाई दी और परिवार पर अत्यन्त तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा। वही दबाव परिस्थितियों को उस कगार तक ले गया जहाँ भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। इस एक क्षण ने न केवल एक जीवन छीना, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। यह घटना सिर्फ मानवता पर एक चोट नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण भी है जिसमें हम अपने समय की सबसे बड़ी विडंबना को साफ देख सकते हैंकृ कानून कुछ कहता है, समाज कुछ और। व्यक्ति की स्वतंत्रता एक दिशा में जाती है, जबकि परंपराएँ दूसरी दिशा में खींचती हैं। इन दोनों के बीच जो परिवार खड़ा होता है, वह अक्सर दोनों ओर से घायल होता है। कानून वयस्कता की उम्र तय कर देता है, पर वह ग्रामीण समाज की संवेदनात्मक संरचना, परिवार की प्रतिष्ठा, और सामुदायिक दबाव को नहीं समझता। वहीं समाज स्वतंत्रता के अधिकार को "अवज्ञा" या "विद्रोह" की तरह देखता है और परिवार पर ऐसी जिम्मेदारियाँ डाल देता है जिन्हें निभाना असंभव है। परिवार ही इस संघर्ष का सबसे बड़ा पीड़ित बनता है। बेटी का गांव छोड़कर जाना, रिश्तेदारों की टिप्पणियाँ, पंचायत का दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा का संकटकृये सभी घटनाएँ एक घर को भीतर से हिलाकर रख देती हैं। कानून परिवार से लड़की को स्वीकार करने का संदेश देता है, जबकि समाज उसे अस्वीकार करने का दबाव डालता है। ये दोनों ताकतें परिवार को दो हिस्सों में चीर देती हैंकृएक हिस्सा जिसे मन ने स्वीकार कर लिया है, और दूसरा हिस्सा जिसे समाज स्वीकार नहीं करने देता। ऐसे में विवेक धुंधला पड़ जाता है और भावनाएँ निर्णयों पर हावी होने लगती हैं। इस घटना का सबसे भयावह पहलू यह था कि सोशल मीडिया पर 95 प्रतिशत टिप्पणियाँ इस हत्या को "सही" ठहरा रही थीं। यह केवल कुछ व्यक्तियों की राय नहीं, बल्कि समाज में पनप रही एक खतरनाक सामूहिक सोच का संकेत है। जब कोई समाज अपनी भावनाओं और परंपराओं के दबाव में हत्या जैसे अपराध को भी न्याय मानने लगे, तो यह किसी भी सभ्य व्यवस्था के लिए अत्यन्त गंभीर स्थिति है। कानून की शक्ति तभी तक है जब तक समाज उसे नैतिक समर्थन देता है। जब समाज हिंसा को नैतिक ठहराने लगे, कानून कमजोर नहीं, बल्कि अप्रासंगिक हो जाता है। और यही स्थिति किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। विवाह की स्वतंत्रता का प्रश्न भी इस घटना में नए दृष्टिकोण से उभरता है। भारतीय कानून मानता है कि 18 और 21 वर्ष की उम्र में व्यक्ति परिपक्व और स्वतंत्र निर्णय लेने योग्य होता है। पर क्या वास्तव में यह उम्र जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिना परिवार के अनुभव, बिना सामाजिक समझ, बिना भविष्य की जिम्मेदारियों को समझे लेने के लिए पर्याप्त है? भारतीय परिवार व्यवस्था में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मामला नहीं होता, यह दो परिवारों, रिश्तों और समाजों का मामला होता है। ऐसे में कम आयु में किया गया आवेगपूर्ण निर्णय केवल व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करता है। यही कारण है कि कई लोग तर्क देते हैं कि विवाह के लिए माता–पिता की सहमति आवश्यक होनी चाहिएकृकम से कम 30 वर्ष की आयु तक। यह विचार सामाजिक अनुभवों से उत्पन्न है, पर संवैधानिक दृष्टि से कठिन है। यदि माता–पिता की सहमति अनिवार्य कर दी जाए, तो यह युवाओं पर अत्यधिक दबाव और कई मामलों में दमन को भी जन्म दे सकता है। फिर भी यह भी सच है कि परिवार से विमुख होकर किए गए विवाहों के परिणामों का सबसे बड़ा बोझ परिवारों को ही उठाना पड़ता है। यह द्वंद्व इतना गहरा है कि कोई भी पक्ष न पूरी तरह सही ठहराया जा सकता है, न पूरी तरह गलत। समाज अक्सर कहता है कि लड़की ने "परिवार की कई हत्याएँ कर दीं"कृयह भाषा कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक है। कानून भावनात्मक मृत्यु को अपराध नहीं मान सकता। पर परिवार इसे वास्तविक समझता है क्योंकि वे इसे प्रत्यक्ष जीते हैं। यही वह खाई है जिसे पाटना सबसे कठिन है। कानून कहता है निर्णय व्यक्तिगत है; समाज कहता है निर्णय सामूहिक है। और इन्हीं दो कथनों के बीच वह परिवार टूट जाता है जिसके इर्द–गिर्द इस तरह की घटनाएँ जन्म लेती हैं। इस मामले में सबसे अधिक नुकसान उसी परिवार का हुआ जिसने न अपराध चुना, न विद्रोह। लड़की की जान चली गई, भाई का जीवन जेल में समाप्त, माता–पिता ने एक बेटी और एक बेटे दोनों को खो दिया, घर की आर्थिक–सामाजिक नींव हिल गई, बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो गया। जबकि समाज के लिए यह महज चर्चा का विषय रह गया, और सरकार के लिए सिर्फ एक केस फाइल। प्रश्न यह है कि सरकार क्या कर सकती है? भागकर विवाह पर रोक समाधान नहीं है, पर इस प्रक्रिया में सुधारों की आवश्यकता है। विवादित विवाह से पहले अनिवार्य परामर्श, परिवारदृयुवा मध्यस्थता, पंचायतों के अधिकारों पर स्पष्ट सीमा, और स्कूल–कॉलेजों में सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षाकृये सभी कदम जरूरी हैं। न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाओं को भी परिवार की सामाजिक पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। फिर भी सरकार और कानून दोनों अकेले समस्या हल नहीं कर सकते। जब तक समाज संवाद को हिंसा से ऊपर नहीं रखेगा, जब तक परिवार गुस्से से ऊपर संवाद को नहीं चुनेगा, और जब तक युवा आवेग को निर्णय का आधार बनाना बंद नहीं करेंगेकृ तब तक ऐसी त्रासदियाँ रुकने वाली नहीं हैं। आज़ादी का अर्थ स्वेच्छाचार नहीं, और परंपरा का अर्थ दमन नहीं। दोनों के बीच संतुलन ही सभ्यता का आधार है। अंततः यही समझना होगा कि कानून और समाज की लड़ाई में जीत किसी की नहीं होतीकृ हार हमेशा एक इंसान और एक परिवार की ही होती है।

शेख हसीना को मृत्युदंड : दक्षिण एशियाई कूटनीति में भारत की नई चुनौती

बांग्लादेश के न्यायिक संकट और भारत का कूटनीतिक संतुलन

–डॉ. सत्यवान सौरभ

बांग्लादेश की राजनीति में अभूतपूर्व उथल–पुथल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश के न्यायाधिकरण द्वारा मृत्युदंड सुनाया जाना केवल एक अदालती फैसला नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई भू–राजनीतिक परिदृश्य को हिला देने वाला ऐतिहासिक घटना–क्रम है। यह सजा उस समय सुनाई गई जब हसीना पहले से ही भारत में राजनीतिक शरण जैसी स्थिति में रह रही थीं और बांग्लादेश में उनकी सरकार के विरोध में विस्तृत जन–आक्रोश तथा हिंसक आंदोलनों की पृष्ठभूमि मौजूद थी। इस फैसले ने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और शासन की स्थिरता को तीव्र विवाद के केंद्र में ला दिया है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह स्थिति भारत को किस प्रकार गहरे कूटनीतिक द्वंद्व में धकेल रही है, जहाँ हर कदम क्षेत्रीय समीकरणों और द्विपक्षीय हितों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। भारत के लिए सबसे पहली चुनौती यह है कि वह इस फैसले पर कैसी आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज करे। भारत बांग्लादेश का सबसे नजदीकी और सबसे बड़ा साझेदार देश है, जिसके साथ सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, सीमा–प्रबंधन, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक अन्तःसंबंध जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत किसी भी प्रकार की खुली निंदा या समर्थन का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकार, न्यायिक निष्पक्षता और राजनीतिक स्थिरता के सिद्धांतों को भी साथ में लेकर चलना है, जो उसे क्षेत्रीय नेतृत्व के मानक पर कसते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप–नही–करने की नीति भी भारत के लिए अनिवार्य वास्तविकता है। यही कारण है कि भारत के कूटनीतिक वक्तव्यों का स्वर अत्यंत संयत, सावधान और संतुलित रहा है। भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती शेख हसीना की सुरक्षा और उनके प्रत्यर्पण की संभावित मांग है। हसीना लंबे समय से भारत में सुरक्षित हैं और बांग्लादेश की नई सत्ता–व्यवस्था व न्यायाधिकरण द्वारा उनका प्रत्यर्पण माँगा जाना लगभग निश्चित है। लेकिन भारत–बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में राजनीतिक अपराध अपवाद का स्पष्ट उल्लेख है, जो भारत को कानूनी आधार देता है कि वह हसीना को बांग्लादेश भेजने से इनकार कर सके। इसके अतिरिक्त, यदि भारत उन्हें प्रतिपक्षीय हिंसा या पक्षपातपूर्ण मुकदमे का शिकार मानता है, तो प्रत्यर्पण देना भारत के मानवाधिकार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। किंतु इससे बांग्लादेश सरकार के साथ तनाव बढ़ सकता है, और भारतीय कूटनीति को इसे अत्यंत सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। भारत को इस स्थिति का तीसरा बड़ा आयाम क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में देखना आवश्यक है। भारत और बांग्लादेश लगभग चार हजार किलोमीटर लंबी साझा सीमा साझा करते हैं, जहाँ अशांति फैलने या राजनीतिक हिंसा बढ़ने से सीमा सुरक्षा, सीमा–पार अपराध, अवैध आवागमन, शरणार्थी प्रवाह और कट्टरपंथी समूहों की गतिविधियों में वृद्धि की आशंका है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम जैसे राज्यों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश की स्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी अन्य राष्ट्रीय रणनीति के लिए। इसलिए भारत चाहता है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सामाजिक शांति और प्रभावी शासन जितनी जल्दी बहाल हो सके, उतना बेहतर है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि बांग्लादेश की राजनीति में अस्थिरता से भारत–बांग्लादेश आर्थिक संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापारिक विनिमय, औद्योगिक सहयोग, बिजली और गैस पाइपलाइन परियोजनाएँ, बंदरगाह विकास समझौते, सीमा–पार रेल और सड़क कनेक्टिविटी, और कई आर्थिक गलियारे चल रहे हैं। यदि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट लंबा खिंचता है, तो इन परियोजनाओं की गति धीमी पड़ सकती है, निवेश वातावरण प्रभावित हो सकता है और व्यापार बाधित हो सकता है। यह विशेष रूप से उस समय और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब क्षेत्रीय शक्तियाँकृविशेषतः चीनकृबांग्लादेश में सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हों। चीन–बांग्लादेश संबंध भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। चीन ने बांग्लादेश में बड़े–बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, समुद्री समझौतों और सामरिक ठिकानों के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया है। यदि राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भारत–बांग्लादेश संबंध कमजोर पड़ते हैं, तो यह चीन को एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। इसलिए भारत को ऐसी किसी भी स्थिति से बचना होगा जहाँ उसकी तटस्थता या हसीना के प्रति सहानुभूति को नई बांग्लादेशी सत्ता भारत–विरोधी या अपना–नुकसान समझने लगे। भारत के लिए यह पूर्णतः रणनीतिक चुनौती हैरू उसे लोकतंत्र और न्यायिक निष्पक्षता का समर्थन भी करना है और अपनी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा व सामरिक हितों की रक्षा भी। अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों की नीतियाँ भी इस घटनाक्रम को और जटिल बनाती हैं। अमेरिका ने कई बार बांग्लादेश में चुनावी पारदर्शिता और मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जताई है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश के राजनीतिक उद्देश्यों को भारत–विरोधी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर सकता है। भारत इस त्रिकोणीय दबाव के बीच संतुलन साधते हुए एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसमें वह न तो क्षेत्रीय शक्ति–नीतियों में पीछे हटे और न ही किसी प्रत्यक्ष विवाद में उलझे। भारत का यह संतुलन उसके व्यापक दक्षिण एशिया दृष्टिकोण को भी परिभाषित करता है। लोग–से–लोग संपर्कों और सांस्कृतिक जुड़ावों पर भी इस घटनाक्रम का असर पड़ सकता है। लाखों बांग्लादेशी भारत में कार्यरत हैं, पढ़ते हैं, आते–जाते हैं और सांस्कृतिक विनिमय करते हैं। यदि बांग्लादेश की नई सत्ता भारत के रुख से असंतुष्ट होती है तो इन लोगों पर दबाव बढ़ सकता है, जो दोनों देशों के सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण को अस्थिर कर सकता है। वहीं भारत में रहने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी अधिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सार रूप में देखा जाए तो शेख हसीना को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा बांग्लादेश के भीतर गहरा राजनीतिक–न्यायिक संकट है, लेकिन इसका प्रभाव केवल वहीं सीमित नहीं रहता; यह पूरे दक्षिण एशिया के कूटनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक ताने–बाने को प्रभावित करता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश में स्थिरता, लोकतंत्र और न्यायपूर्ण शासन की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो। भारत की कूटनीति को धैर्य, सूझबूझ और उच्चतर संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना होगा। अंततः, यह घटनाक्रम भारत को यह याद दिलाता है कि पड़ोसी देशों की घरेलू राजनीति कभी अकेली नहीं होती; वह सीमाओं से परे प्रभाव डालती है और शक्ति–संतुलन की नई सिरों पर प्रश्न उठाती है। भारत को ऐसे समय में वही भूमिका निभानी है जिसकी उम्मीद एक जिम्मेदार, लोकतांत्रिक और क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता शक्ति से की जाती हैकृ संवेदनशील लेकिन दृढ़, संतुलित लेकिन सिद्धांतनिष्ठ, और तटस्थ लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से समृद्ध।

दधीचि और कर्ण के देश में अंगदान को लेकर कंजूसी

देश में अतीत में अंगदान से जुड़े कई उदाहरण व आदर्श मौजूद हैं लेकिन अंगदान की दर विदेशों के मुकाबले बहुत कम है। मृत्यु के बाद दूसरों के शरीर के लिए काम आ जाने वाले अंगों को दान देने वालों की संख्या बहुत मामूली है। दरअसल अंगदान के प्रति हमारे समाज में संकोच, अशुचि–भाव और भय बहुत गहरे हैं। जागरुकता की कमी के अलावा इसके पीछे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और संस्थागत व प्रशासनिक जटिल कारण भी हैं। यह सोचने वाली बात है कि जिस देश में परोपकार के लिए अपनी हड्डियों तक का दान दे देने वाले महर्षि दधीचि हुए हैं और अपनी जान की परवाह न करते हुए कवच और कुंडल का दान कर देने वाले अंगराज कर्ण हुए हैं, उस देश में आखिर 'अंगदान–महादान' सिर्फ एक नारा ही क्यों है? सचमुच अफसोस की बात है कि इतिहास में दानियों से भरे पड़े देश भारत का अंगदान के मामले में दुनिया में सबसे निचला स्थान क्यों है? दरअसल इसका उत्तर सिर्फ अंगदान के प्रति जागरुकता की कमी भर नहीं है बल्कि इसके पीछे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और संस्थागत व प्रशासनिक जटिल कारण भी हैं। मौजूदा हकीकत यह है कि मृत्यु के बाद दूसरों के शरीर के लिए काम आ जाने वाले अंगों को दान देने वालों की संख्या ऊंगलियों पर गिनने लायक है। दरअसल अंगदान के प्रति हमारे समाज में संकोच, अशुचि–भाव और भय बहुत गहरे हैं। जैसा कि हम सब अपनी पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं कि महर्षि दधीचि ने देवताओं को दानवों से रक्षा करने के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था ताकि उनसे बनने वाले ब्रानुष से वक्रासुर नामक राक्षस का वध ा किया जा सके। लेकिन आज किसी व्यक्ति के 'ब्रेन–डेड' हो जाने के बाद उसके परिजनों से उसके अंगों का दान करवाने के लिए हामी भरवाना बेहद कठिन है। इसलिए आदर्श हमारे चाहे जितने बड़े हों, वास्तविकता में हम उनके कहीं आसपास भी नहीं फटकते। दरअसल अंगदान से डरने की सबसे बड़ी वजह मृत्यु से जुड़े मिथक और मनोवैज्ञानिक भय हैं। इसके चलते लोग चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को पूरा रखा जाए। यह भी धारणा है कि मृत्यु के बाद शरीर को चीरना महापाप है। एक नहीं अनेक मिथक हैं जिस कारण भारत के लोग फिर वह चाहे जिस धर्म या समुदाय से नाता रखते हों, अंगदान करने से घबराते हैं। इन मान्यताओं और विश्वासों के कारण ही लोग मर जाने के बाद भी अपने परिजनों के अंगों का दान नहीं करते। भारत में अगर लोग अपने किसी परिजन के ब्रेन–डेड हो जाने के बाद भी उसके शारीरिक अंगों का दान करने से कतराते हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ब्रेन–डेड की अवधारणा को सही से न समझ पाना भी है। जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में अंगदान का सबसे बड़ा स्रोत ब्रेन–डेड मरीज ही होते हैं। जबकि भारत में ऐसे लोगों को 'अभी जीवित है' मानकर उसके अंगों के दान से पीछे हट जाते हैं। भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग अगर किसी मरीज के हृदय की धड़कन चल रही हो और वैज्ञानिक रूप से भले उसकी ब्रेन–डेथ हो चुकी हो, फिर भी उसे मरा नहीं समझते। कहीं न कहीं मन में उम्मीद बाकी रहती है कि शायद ब्रेन–डेड व्यक्ति दोबारा जीवित हो जाए। दरअसल अंगदान के मामले में सबसे बड़ी बाध ा यही भावुक स्थिति है। भारत में अंगदान को लेकर सिर्फ यहां के लोग ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर हमारे यहां के अस्पताल भी इसके प्रति उदासीन रहते हैं। यही वजह है कि अंगदान को लेकर अस्पतालों में भी बड़ी धीमी और कई बार नकारात्मक प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्योंकि आधुनिक अंगदान की वैज्ञानिक–प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसलिए अगर अस्पताल इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नहीं अदा करेंगे, तो उसे व्यावहारिक कर पाना संभव नहीं। सबसे पहले तो अस्पतालों में ब्रेन–डेड की ठोस घोषणा बहुत मुश्किल से होती है। फिर अस्पतालों में ट्रेंड ट्रांसप्लांट को–आर्डिनेटर का भी अभाव होता है और अगर किसी दूसरे अस्पताल से अंग प्राप्त करने की बात हो तो वहां से जरूरत की जगह तक अंग के पहुंचने के लिए साफ सुथरा, निर्बाध और सटीक रास्ता नहीं होता। वैसे 2023–24 की एक वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5,651 पुरुष और 9,784 महिलाएं ही जीवित अंगदान दाता थीं और साल 2024 में देश के अंदर 18,911 लोगों को अंग प्रत्यारोपण किये गये। भारत में मृत दाताओं का औसत प्रति दस लाख की आबादी में 0.5 है। जबकि भारत में अकेले हर साल 63 हजार लोगों को गुर्दा प्रत्यारोपण की ही जरूरत होती है और लगभग 22 हजार लोगों को हर साल लिवर प्रत्यारोपण की जरूरत होती है। लेकिन देश में अंगदान की चेतना और रुचि न होने के कारण ज्यादातर लोगों की जान बिना प्रत्यारोपण के ही चली जाती है। दूसरे देशों का इतिहास भले अंगदान देने वाले महापुरुषों से भरा न पड़ा हो लेकिन वहां भारत के मुकाबले बहुत बड़ी संख्या में ब्रेन–डेड लोगों के परिजनों द्वारा उनके अंगों का दान करने की परंपरा है। सबसे ज्यादा स्पेन में प्रति 10 लाख की आबादी में 50 ब्रेन–डेड लोगों के परिजनों द्वारा उनके अंगों को दान दे दिया जाता है। इसी तरह कोरिया में 39.96, जापान में 14.53 का अंगदान होता है। कुल मिलाकर भारत में जहां प्रत्यारोपण की दिन पर दिन जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और प्रति 10 लाख लोगों में हमारे यहां सबसे ज्यादा अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है। लेकिन भारत में अंग का दान देने वाले लोग मुट्ठीभर भी नहीं हैं। हम सिर्फ ऐसे मौके पर बार–बार ऐतिहासिक नामों का ही अतीत गुणगान करते रहते हैं। हकीकत में अंगदान से काफी दूर रहते हैं। कई बार जब ऐसे अंगदान सफल हुए हैं, तो उसमें बड़ी भूमिका ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाये गये ग्रीन कॉरिडोर की भी रही है।

सीएम योगी का फरमान, पीड़ितों की शिकायतें सुन जिले में ही निस्तारण कराएं डीएम- एसपी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उनके आवास पर जनता दर्शन के दौरान लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं का जल्द समाधान करायें। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक बयान के अनुसार 'जनता दर्शन' का आयोजन सोमवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुआ।'जनता दर्शन' में प्रदेश भर से 52 से अधिक फरियादी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हर फरियादी के पास स्वयं पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और निराकरण के निर्देश दिए। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वह पीड़ितों की शिकायतें सुनकर जनपद में ही उनका निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपदों में सभी विभागों के द्वारा

पीड़ितों की शिकायतें सुनकर निर्धारित समयावधि में समाधान कराया जाए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अभिभावकों के साथ आए बच्चों को दुलारा, उन्हें चॉकलेट दी। मुख्यमंत्री के 'जनता दर्शन' के दौरान आर्थिक सहायता, अवैध कब्जे, बिजली, शिक्षा, पुलिस आदि से जुड़ी शिकायतों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वह जनपद स्तर पर सभी फरियादियों की शिकायतें सुनकर उनका निराकरण कराएं। 'जनता दर्शन' में गोरखपुर, शामली, झांसी, कन्नौज आदि जनपदों से पीड़ित पहुंचे थे। सभी ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सेवा और सुरक्षा ही सरकार का संकल्प है, सरकार हर जरूरतमंद की सहायता के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर प्रदेशवासियों की हर उचित परेशानी का निरंतर निदान कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाता रहेगा।

हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 ये शाम मस्तानी सांग पर झूमे श्रोता

संवाददाता

लखनऊ। कानपुर रोड आशियाना क्षेत्र स्मृति उपवन में चल रहे माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह व रणवीर सिंह, गुंजन वर्मा और हेमू चौरसिया ने सांस्कृतिक संध्या का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 पांचवी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी एवम सहयोगी ने अपने–अपने सुरमई आवाजों से महोत्सव की शाम को यादगार बनाया। सांस्कृतिक संध्या का आरंभ ये शाम मस्तानी. .... उस्मान सिद्दीकी, अभिषेक द्विवेदी और अभिनव पांडे ने अपनी खनकती आवाजों से बिखेरा जादू। तदुपरांत आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले.. ...अकदस कछ्रेशी, आपके प्यार में हम संवरने लगे...।

'फन का रॉकस्टार सीजन थ्री ने लखनऊ में मचाया धमाल'

संवाददाता

लखनऊ। शहर के पसंदीदा शॉपिंग डेस्टिनेशन फन रिपब्लिक मॉल में तीन दिवसीय 'फन का रॉकस्टार सीजन–3' का सफल आयोजन किया गया। इस म्यूजिक फेस्ट–कम–कम्पटीशन में शहर के स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल–तीनों कैटेगरी के बैंड्स ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दिल सम्भल जरा, वो भी अपने न हुए, प्रीत की लत, बादशाह ओ बादशाह जैसे गानों ने माहौल को संगीतमय कर दिया। इसके बाद शिव तांडव ने माहौल को गर्म कर दिया और लोगों के हाथ अपने आप भोलेनाथ की श्रद्धा में बंध गए। स्कूल बैंड की परफॉर्मेंस में विजेता दृ इश्क एक्सप्रेस (ला मार्टिनियर), पहला उपविजेता दृ नूरे (जयपुरिया), दूसरा उपविजेता दृ एलपीसी बैंड रेंजर्स (एलपीसी स्कूल) बात करें अगर कॉलेज बैंड की तो विजेता दृ एनम कारा द बैंड (भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय) पहला उपविजेता दृ हाई नोट द बैंड (इंटीग्रल यूनिवर्सिटी) दूसरा उपविजेता – अलंकार (आईईटी) और अंत में प्रोफेशनल बैंड में विजेता दृ फितूर बैंड, पहला उपविजेता टीम नाद रोग, दूसरा उपविजेता आरएस म्यूजिक बैंड और वाणी लाइव बैंड रहे। प्रथम विजेता को 15,000, द्वितीय विजेतको 10,000 एवं तृतीय विजेता को 5,000 साथ ही आकर्षक ट्रॉफियाँ भी प्रदान की गईं। फन रिपब्लिक मॉल के जनरल मैनेजर अश्विनी सिंह ने कहारू 'भारत में संगीत का अपना विशेष महत्व है। हमारी संस्कृति में संगीत हमेशा से प्रेरणा और उत्साह का माध्यम रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मॉल में 'फन का रॉकस्टार सीजन–3' का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल बैंड्स ने शानदार प्रदर्शन किया। मॉल आगे भी ऐसे संगीतमय कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, ताकि शहर के लोगों को कला और संगीत का बेहतरीन अनुभव मिलता रहे।

यूपी की राज्यपाल को 30 हजार स्काउट ने सलामी दी

डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में सार्क देशों के स्काउट–गाइड का जंबूरी

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में नेशनल जंबूरी मनाया जा रहा है। यहां 30 हजार स्काउट–गाइड का जमावड़ा है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को सभी स्काउट ने सलामी दी। इसमें सऊदी अरब, नेपाल, श्री लंका, मालदीव के स्काउट–गाइड शामिल हैं। जंबूरी के दौरान डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में एडवेंचर, ड्रोन शो से दिन गुलजार हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से शाम सजी हुई है। आज (24 नवंबर को) राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तिरंगा फहराकर इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया। विश्वभर के स्काउट–गाइड इकट्ठा होकर सेलिब्रेशन करते हैं। इसी सेलिब्रेशन को जंबूरी कहा जाता है। 1920 से जंबूरी की शुरुआत हुई। यह चार साल में एक बार एक हफ्ते के लिए आयोजित किया जाता है। जंबूरी के दौरान सभी स्काउट–गाइड अपने देश, क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार प्रदर्शन करते हैं। साथ ही स्काउट–गाइड के नियमों के अनुसार जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके एडवेंचर भी दिखाते हैं। पहला जंबूरी यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उसके बाद चौथा जंबूरी भारत में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। उसके बाद से नेशनल जंबूरी भी मनाया जाने लगा। 19वें नेशनल जंबूरी की मेजबानी यूपी (लखनऊ) को मिली है। जम्बूरी मैदान में सहभागी राज्यों के साथ विदेशी दलों ने भव्य परेड मार्चपास्ट प्रस्तुत किया। सभी टुकड़ियों ने अनुशासित कदमताल के साथ मुख्य अतिथियों को सलामी दी। रंग–बिरंगी वेशभूषा, सांस्कृतिक प्रतीक और सुव्यवस्थित परफॉर्मेंस ने पूरे समारोह को खास आकर्षण प्रदान किया। राज्यपाल को सऊदी अरब, नेपाल, श्री लंका, मालदीव के स्काउट ने सलामी दी। जंबूरी मैदान में सहभागी राज्यों के साथ विदेशी दलों ने भव्य परेड मार्चपास्ट प्रस्तुत किया। सभी टुकड़ियों ने अनुशासित कदमताल के साथ मुख्य अतिथियों को सलामी दी। रंग–बिरंगी वेशभूषा, सांस्कृतिक प्रतीक और सुव्यवस्थित परफॉर्मेंस ने पूरे समारोह को खास आकर्षण दे रहे हैं।

स्थानीय सांसद, मंत्री, महापौर और क्षेत्रीय विधायक से मांग

संवाददाता

लखनऊ। सांसद लखनऊ एवं रक्षा मंत्री भारत सरकार, नगर विकास मंत्री,महापौर लखनऊ, विधायक ओ पी श्रीवास्तव जी पूर्वी विधान सभा, पार्षद सम्बंधित क्षेत्र आदि जिम्मेदार विभाग जलकल, नगर निगम व जल निगम आदि को सम्बोधित पत्र के माध्यम से इन्दिरा नगर जन समस्या समाधान समिति,इन्दिरा नगर लखनऊ के अध्यक्ष शशिकुमारमिश्र, महामंत्री–संतोष वाजपेई ने क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग की है। पत्र के माध्यम से कहा गया कि पूर्वी लखनऊ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत इन्दिरा नगर सेक्टर 11 जोन 7 के अधीन वार्ड इस्माइल गंज प्रथम, द्वितीय तथा वार्ड बाबूजगजीवन राम के मोहल्ले लाजवन्ती नगर, शंकरपुरी कालोनी,मथुरा बिहार, हरिहर नगर, सन्तपुरम,राजीव नगर आदि में जहा पिछले 10 वर्षो से लगातार यहां के हजारो हजार निवासियो द्वारा मांग की जाती रही परन्तु हर घर जल योजना के अंतर्गत वाटर लाईन पडी है या नही से पानी का कनेक्शन लोगो के यहां न हो सका। इस क्षेत्र में कोई ट्यूबवेल, पानी की टंकी भी नही बन सकी,बनायी जाए। इस क्षेत्र में अवैध भैसो,गाय आदि के तबेले होने के कारण सफाई व्यवस्था भी प्रभावित रहती है,उन्हे अभियान लगा कर हटाया जाए।

एसआईआर पर शोर मचाने वाले दलों के मन में चोर : केशव प्रसाद मौर्य

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि ''एसआईआर को लेकर शोर मचाने वाले दलों के मन में चोर है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सह प्रभारी रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर पोस्ट किया,''मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर शोर मचाने वाले दलों के 'मन में चोर है। बिहार ने साबित कर दिया है कि उनका पक्ष कमजोर है। बिहार के

हाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने प्रचंड जीत हासिल की और 'इंडिया गठबंधन के दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने एसआईआर को लेकर लगातार सरकार और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है।

संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, शिनाख्त और मौत के कारणों की जांच जारी

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के बंथरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर रोड से दादूपुर गांव जाने वाली सड़क के किनारे एक होटल के पास यह शव पड़ा मिला। सुबह सड़क किनारे संदिग्ध हालत में शव देखकर राहगीरों ने बंथरा पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से युवक की पहचान कराने

का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। उसने काले रंग की जींस पैंट और काले रंग का स्वेटर पहन रखा था। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और पिछले 5–6 दिनों से इलाके में घूम रहा था। युवक की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि मौत की सही वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। फिलहाल, मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसकी तस्वीरें आसपास के सभी थानों में भेजी गई हैं।

मकान में लगी आग,फायर बिग्रेड ने डेढ़ घंटे में काबू पाया

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर में एक मकान में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। घटना की सूचना फायर स्टेशन इंदिरानगर को मिली। जिसके बाद एफएसओ की नेतृत्व में फायर यूनिट मौके पर पहुंची। डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। सीएफओ अंशु मित्तल ने बताया सोमवार दोपहर करीब 12.30 बजे इंदिरानगर क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिकी। फायर टीम ने पहुंचकर देखा कि शकुंतला शर्मा के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में आग धधक रही थी। घर में वेंटिलेशन न होने की वजह से पूरे मकान में धुआं भर गया।

आदर्श व्यापार मंडल की बैठक, संगठन को मजबूत बनाने की तय हुई रणनीति

सरकारी खरीदारी में व्यापारियों को प्राथमिकता देने की मांग

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आदर्श व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक हुई। अयोध्या रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने की। बैठक में संगठन को अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ सहित प्रदेश की सभी क्षेत्रीय इकाइयों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्गठन और विस्तार किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के व्यापार को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ाना संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आदर्श व्यापार मंडल प्रत्येक व्यापारी को संगठन से जोड़ेगा और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए पूरी क्षमता से संघर्ष करेगा। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि प्रदेश में होने वाली सभी सरकारी खरीद में स्थानीय व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे उनका व्यापार सशक्त हो सके। बैठक में व्यापारियों

ने 'ओडीओपी' की तर्ज पर 'एलडीएलटी योजना' (लोकल डिस्ट्रिक्ट लोकल ट्रेडर) लागू करने की मांग सरकार से किया है। ताकि प्रत्येक जिले के स्थानीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिल सके।बैठक के दौरान नगर निगम द्वारा दुकानों को हाउस टैक्स बकाया को लेकर सील किए जाने पर नाराजगी जताई। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम बाजारों से अतिक्रमण हटाने में उदासीन रहता है और केवल राजस्व वसूली पर ध्यान देता है। व्यापारियों ने यातायात जाम, बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण, हाउस टैक्स के गलत बिल और लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़ी समस्याओं को उठाया। समिति ने इन सभी मुद्दों पर आंदोलन और संघर्ष की रणनीति बनाने पर भी सहमति जताई।

4 करोड़ 64 लाख रुपये की विकास योजना से निखरेगा लखनऊ का प्राचीन रविदास मंदिर

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अलीगंज स्थित प्राचीन रविदास मंदिर को निखारने का 4.64 करोड़ रुपए की स्वीकृत योजना के तहत आरंभ हो चुका है। सौंदर्यीकरण, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से पूरे परिसर को नया स्वरूप दिया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सोमवार को बताया प्रदेश का पर्यटन विभाग राजधानी लखनऊ में धार्मिक पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से धार्मिक स्थलों के समग्र विकास पर तेजी से कार्य कर रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और मंदिर के स्थानीय महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत सड़क मरम्मत, पेयजल सुविधा, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच तथा परिसर के जर्जर हिस्सों के पुनरुद्धार जैसी प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि भक्तों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर अनुभव उपलब्ध कराया जा सके। अलीगंज स्थित रविदास मंदिर राजधानी के प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर अंकित स्थापना वर्ष 1924 इस बात का प्रमाण है कि यह धरोहर

101 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। यह स्थान लंबे समय से स्थानीय समुदाय के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रहा है। परिसर में स्थित तीन प्राचीन समाधियों में से एक मंदिर निर्माण से भी पूर्व की बताई जाती है, जबकि अन्य दो समाधियां बाबा लीलादास और बाबा टिकाईदास से संबंधित हैं, जिन्होंने वर्षों तक यहां सेवाएँ दीं। स्थानीय समुदाय का मंदिर से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। मंदिर के बाहर वर्षों से जूते–चप्पल की मरम्मत का कार्य करने वाले नौमी लाल बताते हैं कि उनके पिता भी यहीं कार्य किया करते थे। वहीं मिष्ठान विक्रेता भोलानाथ के अनुसार उनके बाबा ने 1931 में यहां दुकान लगानी शुरू की थी। संत रविदास जयंती के अवसर पर यहां हर वर्ष बड़े पैमाने पर आयोजन होते हैं, जिनमें स्थानीय लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। व्यापारियों का मानना है कि सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा। सिंह ने कहा कि अलीगंज स्थित प्राचीन रविदास मंदिर का समेकित विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। चार करोड़ 64 लाख रुपये की स्वीकृत परियोजना के तहत सौंदर्यीकरण, अवसंरचनात्मक सुधार तथा आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल भक्तों को बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों से ऊर्जा निगमों में बिगड़ रहा वातावरण

संवाददाता

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि निजीकरण के एकतरफा निर्णय के विरोध में विगत एक वर्ष से शान्ति पूर्वक आंदोलन रत बिजली कर्मियों का बिना कारण उत्पीड़न कर पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन ने ऊर्जा निगमों में कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया है।संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया है कि वह प्रभावी हस्तक्षेप कर निजीकरण का फैसला निरस्त कराने की कृपा करें और पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन को निर्देश दें कि बिजली कर्मियों पर अनावश्यक तौर पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त की जाय। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों का प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है और उनके कुशल नेतृत्व में बिजली कर्मी लगातार सुधार में लगे हुए हैं। पिछले एक साल से आंदोलनरत होते हुए भी बिजली कर्मियों ने भीषण गर्मी में 31618 मेगावाट बिजली आपूर्ति कर देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बिजली कर्मियों के प्रयास से हो रहे सतत सुधार का ही परिणाम है कि लगातार छह वर्षों से उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बावजूद पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन बिजली कर्मियों का उत्पीड़न कर कार्य का वातावरण खराब कर रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि उत्पीड़न के नाम पर हजारों अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, संघर्ष समिति के शीर्ष पदाधिकारियों पर स्टेट विजिलेंस की जांच कर झूठी एफआईआर की जा रही है, कार्यालय समय के उपरांत सभा में भाग लेने वाले हजारों बिजली कर्मियों का जिसमें महिलाएं भी शामिल है बड़े पैमाने पर दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर किया गया, पिछले एक साल में कई बार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को परामर्श के नाम पर चेतावनी देकर उनके व्यक्तिगत फाइल में रखा गया। सबसे ताजा उत्पीड़न की घटना यह है कि 87 अभियंताओं को कार्यालय समय के उपरांत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग न लेने के चलते दिए गए परामर्श पत्र के आधार पर उनकी पदोन्नतियां रोक दी गई हैं जो मनमानेपन की इंतिहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन, कार्यालय समय के उपरांत की जा रही गतिविधियों के आधार पर जिस प्रकार बिजली कर्मियों का उत्पीड़न कर रहा है, उससे ऊर्जा निगमों में गुस्सा बढ़ गया है और उसके परिणाम की जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन की होगी। निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 362 वें दिन आज बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

संक्षिप्त

अधिनियम में उपभोक्ता पोस्टपेड व प्रीपेड का विकल्प : आयोग

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं पर बिना अनुमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर थोपे जाने के मामले में उपभोक्ता परिषद की लगातार लड़ाई आखिरकार रंग लाई है। दो दिन पहले जारी हुए बिजली दर (टैरिफ) आदेश में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्मार्टप्रीपेड मीटर की अनिवार्यता विद्युत अधिनियम 2003 में कहीं भी नहीं है, और उपभोक्ता के अधिकार सर्वोच्च हैं। आयोग ने अपने टैरिफ आदेश में कहा है कि विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 तथा त्वै योजना के तहत केवल नए कनेक्शन स्मार्ट,प्रीपेड मीटर के माध्यम से देने की आवश्यकता है। जैसा पावर कॉरपोरेशन कह रहा है लेकिन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) की भाषा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य नहीं बनाती। यानी कि उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड का विकल्प देता है चूँकि इस विषय पर कई राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएँ लंबित हैं, इसलिए आयोग कानूनी स्थिति पर टिप्पणी से परहेज कर रहा है, किंतु स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को प्रीपेड हो या पोस्टपेडमीटर दिया जाना उनका अधिकार है।इस पर, उत्तर प्रदेश राज विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब स्वयं विद्युत नियामक आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों का विकल्प देती है, और यह मामला देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है, तो ऐसे में पावर कॉरपोरेशन किस अधिकार से उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर को उनकी सहमति के बिना अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में परिवर्तित कर रहा है? जबकि देश का राष्ट्रीय कानून उसे पोस्टपेड व प्रीपेड का विकल्प देता है उपभोक्ता परिषद यह भी कहना चाहता है जब तक मामला अदालतों में विचाराधीन है, पावर कॉरपोरेशन को कानून का पालन करते हुए उपभोक्ताओं को विकल्प देना अनिवार्य है। भारत का राष्ट्रीय कानूनकृविद्युत अधिनियम 2003, किसी भी नियम से हमेशा बड़ा होता है। इसलिए वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो कानून में निर्धारित है।उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि पावर कॉरपोरेशन तुरंत उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का विकल्प उपलब्ध कराए।

अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख, कहा, कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है

संवाददाता/लखनऊ। बॉलीवुड अभिनेता के निधन पर सीएम योगी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

भदोही में डाइंग प्लांट की जहरीली गैस से तीन की मौत, एक बेहोश

औराई स्थित निजी कालीन कम्पनी के डाइंग प्लांट में हुआ हादसा
डीएम और एसपी ने बचाव और राहत का लिया जायजा, जाँच के दिए आदेश

बीएनई

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही के औराई स्थित एक निजी कालीन कंपनी में सोमवार वाटर टैंक की सफाई और मोटर पंप ठीक करने के दौरान जहरीली गैस की जद में आने से चार लोग बेहोश हो गए। किसी तरह प्रभावित लोगों को निकाल कर स्थानीय ट्रामा सेंटर लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने तीन मैकेनिकों को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक की हालत खतरे से बाहर बताई गईं है उसका ईलाज निजी ट्रामा सेंटर में चल रहा है। भदोही जिले के औराई के उगापुर स्थित एक चर्चित कालीन कंपनी के डाइंग प्लांट में सोमवार को वाटर टैंक की सफाई और मोटर पंप करने के दौरान एक कामगार गिर गया। जबकि उसे बचाने तीन लोग और टैंक में उतरे उसी इसी दौरान जहरीली गैस रिसाव होने से चारों लोग उसकी चपेट आ गए और प्लांट के अंदर बेहोश हो गए। बाद में सभी को किसी तरह निकाल कर निजी ट्रामा सेंटर लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक का ईलाज चल रहा है। इस हादसे में जिन तीन लोगों की मौत हुई है जिसमें शिवम दुबे पुत्र विजय कांत दुबे निवासी कोठरा थाना औराई जनपद भदोही, राम सूरत यादव उर्फ जय मूरत यादव (55) पुत्र हरिहर नाथ यादव निवासी कोठरा थाना औराई,

शीतला प्रसाद मिश्रा पुत्र शिव पूजन मिश्रा (50) निवासी दयालपुर थाना औराई जनपद भदोही शामिल हैं। सूर्या हॉस्पिटल में इलाजरत कर्मी राज किशोर तिवारी पुत्र चंद्रशेखर तिवारी निवासी कन्धवार थाना रामपुर जनपद सीधी (मध्यप्रदेश) जिसकी स्थिति स्थिर है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शैलेश कुमार, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने घटनास्थल का दौरा किया और राहत एवं बचाव के बारे में जानकारी लिया। जिलाधिकारी निजी ट्रॉमा सेंटर भी गए जहां हादसे के पीड़ित एक व्यक्ति का इलाज चल रहा था। जिलाधिकारी ने बताया है की जहरीली गैस की जद में आने से तीन लोगों की मौत हुई है। मामले की जांच के लिए श्रम विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। घटना के कारणों का पता चला लगाया जा रहा है कि गैस का रिसाव कैसे हुआ। पूरी मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल घटना बेहद दुखद है। परिजनों की तहरीर पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

एनसीएल खड़िया में अंतर-क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2025 हुई सम्पन्न

बीएनई

सिंगरौली। सिंगरौली स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की खड़िया परियोजना में गत शनिवार को अंतर-क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2025 सम्पन्न हुई। यह प्रतियोगिता 20 नवंबर से 22 नवंबर 2025 तक आयोजित की गयी जिसमें एनसीएल की सभी परियोजना एवं इकाइयों से 12 टीमों से 168 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 15 मैच खेले गए। समापन समारोह के दौरान निदेशक (मानव संसाधन), मनीष कुमार मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित रहे। इस दौरान अपने उद्बोधन में उन्होनें विजेता टीम को बधाई देते हुए खेल को टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व, सहकारिता का सूत्र बताया। इसके अतिरिक्त उन्होने आने वाली पीढ़ी को भी खेल-कूद से जोड़ने हेतु आह्वान किया। इस अवसर पर कंपनी स्तरीय जेसीसी सदस्य- सीएमएस से अजय कुमार, आरसीएसएस से लाल पुष्पराज सिंह, बीएमएस से श्यामधर दुबे, एचएमएस से अशोक कुमार पांडे, सीएमओएआई से सर्वेश सिंह, महाप्रबंधक (खड़िया) के. डी. जैन , परियोजना जेसीसी सदस्य, विभागाध्यक्षगण, स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड मेम्बर्स एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जयंत टीम रही विजेता अंतर-क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच जयंत एवं मुख्यालय की टीमों के बीच खेला गया। इस दौरान जयंत टीम ने शानदार प्रदर्शन के साथ 3-2 से मुख्यालय टीम को हराकर विजेता खिताब अपने नाम किया। प्रतिस्पर्धा के दौरान संतोष वैश्य (जयंत) बेस्ट प्लेयर, राजेन्द्र वैश्य (मुख्यालय) बेस्ट स्कैटर, शशि कुमार वैश्य (मुख्यालय) बेस्ट लिबेरो एवं जगन्नाथ वैश्य (मुख्यालय) बेस्ट स्मैशर बने। गौरतलब है कि एनसीएल द्वारा प्रतिवर्ष अपने कर्मियों का मनोबल बढ़ाने एवं उनके शारीरिक और मानसिक विकास हेतु ऐसी अनेक खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है।

वरूण विहार के लिए 105 बीघा जमीन का लिया गया कब्जा

- आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी वरूण विहार योजना
- 450 बीघा जमीन का हुआ बैनामा, किसानों को 300 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि वितरित

बीएनई

आगरा। आगरा एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित वरुण विहार योजना के लिए एलडीए ने जमीन का कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को एलडीए की टीम ने ग्राम- दोना और तेजकृष्ण खेड़ा में अभियान चलाकर लगभग 105 बीघा जमीन का कब्जा प्राप्त किया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे के पास लगभग 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में वरूण विहार योजना विकसित की जाएगी, जोकि प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना होगी। इसके लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि चिन्हित की गयी है। यहां लगभग 22,403 किसानों से प्राधिकरण के पक्ष में जमीन का बैनामा कराया जाना है। इस पर तेजी से काम चल रहा है और अभी तक किसानों को 300 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि वितरित करते हुए लगभग 450 बीघा जमीन का बैनामा कराया जा चुका है। सोमवार को एसडीओएम0 विराग कवरिया के नेतृत्व में नायब तहसीलदार ज्ञानेन्द्र शुक्ला व उनकी टीम ने मौके पर अभियान चलाकर 105 बीघा जमीन का कब्जा प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि वरूण विहार योजना में कुल 25 सेक्टर होंगे, जिनमें 15 हजार से अधिक भूखण्ड सृजित किये जाएंगे। इससे बड़ी आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी। साथ ही शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लॉजिस्टिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। योजना में 800 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में ग्रीन बेल्ट, पार्क व वॉटर बॉडीज विकसित की जाएगी, जिसमें 01 अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स व सेंट्रल पार्क होगा। इसके अलावा 300 एकड़ क्षेत्रफल में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा।

संक्षिप्त

अनुपमा रामचंद्रन बनीं भारत की पहली महिला स्नूकर विश्व चौंपियन

एजेंसी

नई दिल्ली। 23 वर्षीय तमिलनाडु की खिलाड़ी अनुपमा रामचंद्रन ने भारतीय खेल इतिहास में सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने हांगकांग की तीन बार की विश्व चौंपियन ऑन यी को हराकर आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर (15-रेड) चौंपियनशिप 2025 जीत ली। यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि भारत ने महिला श्रेणी में पहली बार विश्व स्नूकर खिताब पर कब्ज़ा किया है। फाइनल बेहद रोमांचक रहा और अनुपमा ने मुकाबला 3-2 से जीता। निर्णायक फ्रेम में उनका भाग्य भी उनके साथ था। 60-61 के स्कोर पर ऑन यी अंतिम ब्लैक लगाकर जीत सकती थीं, लेकिन उनका शॉट चूक गया और अनुपमा ने यह मौका भुनाते हुए भारत के नाम इतिहास लिख दिया। अनुपमा रामचंद्रन कौन हैं? अनुपमा का जन्म 19 मई 2002 को चेन्नई में हुआ। उनका स्नूकर करियर किसी प्लानिंग से नहीं, बल्कि एक संयोग से शुरू हुआ। सिर्फ 13 साल की उम्र में वे गर्मियों की छुट्टियों में मायलापुर क्लब में एक बिलियर्ड्स वर्कशॉप में पहुंचीं और वहीं से उनकी प्रतिभा की चमक दिखाई देने लगी। क्लब के कोचों और परिवार ने समझ लिया था कि यह बच्ची इस खेल के लिए बनी है। दो साल बाद, मात्र 15 वर्ष की आयु में, उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक स्नूकर खेलना शुरू किया। पढ़ाई और खेल में संतुलन अनुपमा ने विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की और इस समय एमओपी वैष्णव कॉलेज फॉर वुमन से पब्लिक पॉलिसी में पोस्टग्रेजुएशन कर रही हैं।

एसआईआर बिना तैयारी के लागू किया गया है : अखिलेश

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देर सांय जी.टी. रोड़ स्थित एक शादी समारोह में पार्टी कार्यकर्ता के यहां शामिल हुये। उन्होने एसआईआर को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुये कहा कि रिवीजन कहकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। उन्होने तंज कसते हुये कहा कि भाजपा विगत चुनाव में मिली हार के चलते प्रदेश में बिहार मॉडल अपनाने जा रही है। उन्होने कहा कि बीएलओं एवं बीएलए को प्रशिक्षण नहीं मिला है। इस तरह फार्म रिजेक्ट होने एवं वोट कटने की आशंका अधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी भी स्वीकार कर रहे है कि एसआईआर बिना तैयारी के लागू किया गया है। उन्होने साफतौर पर कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट आने पर सपा के मजबूत क्षेत्रों में लगभग 50 हजार वोट कम किए जा सकते है। उन्होने कहा कि मंहगाई बढ़ी है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। भाजपा एसआईआर के बहाने चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कन्नौज सांसद ने कहा कि यही प्रयोग बंगाल में भी करने का प्रयास किया गया किन्तु ममता बनर्जी की सरकार इसका सामना कर रही है। वही उन्होने दुबई में वायुसेना का प्लेन क्रैश होने के मामले में कहा कि देश की छवि को सही होने में काफी समय लग जाएंगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मो. कलीम खान, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे, सयुस प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब हसन आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गूंजे मंगल गान सामूहिक परिणय सूत्र में बंधे 243 जोड़े, मंत्री ने दिया आशीर्वाद

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज पी.एस.एम. कॉलेज, कन्नौज का प्रांगण उल्लास, मंगलध्वनि और शुभकामनाओं से गूंज उठा। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण तथा पार्टी जिलाध्यक्ष श्री वीर सिंह भदौरिया की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस भव्य समारोह में कुल 243 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। इनमें 7 जोड़े मुस्लिम समुदाय के थे, जो इस योजना की सर्वसमावेशी भावना को दर्शाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि "विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का सुंदर मिलन है। आज से आप सभी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। इस सुखमय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य भी करना है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर युवा स्वयं के पैरों पर खड़ा हो, उनके हुनर व शिक्षा का सही दिशा में उपयोग हो और परिवार खुशहाल जीवन जी सके। स्वरोजगार एवं आजीविका बढ़ाने हेतु योगी सरकार अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका लाभ लेकर खुद का स्वरोजगार कर आय के श्रोत बना सकते हैं"। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को आधार से जोड़कर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी किया गया है ताकि पात्र लाभार्थी को बिना किसी बाधा के लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री जी की यह जनहितकारी योजना असंख्य परिवारों

के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। कार्यक्रम में संग्राम सिंह द्वारा प्रस्तुत आल्हा गायन की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि यह लोककला की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने का प्रशंसनीय प्रयास है। पार्टी जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने सभी नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का यह पावन अवसर विविध संस्कृतियों और परंपराओं का अनूठा संगम है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी जोड़ों का दांपत्य जीवन प्रेम, सम्मान और खुशहाली से भरा रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 1,00,000 की धनराशि व्यय की जाती है। इसमें 60,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में, 25,000 मूल्य की उपहार सामग्री (वस्त्र, आभूषणकृचांदी की पायल/बिछिया, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूलकेज, आयरन प्रेस, गद्दे आदि) तथा ₹15,000 प्रति जोड़ा विवाह आयोजन पर व्यय किया जाता है। कार्य में पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, ब्लॉक प्रमुखगण, परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं वर-वधू के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में हर्ष, सद्भाव और उत्सव का वातावरण छाया रहा।

NITCO ने पेश किया- 'कासा ईटर्ना 2025'

भारत के सबसे बेहतरीन मार्बल, मोज़ेक और सरफेस इनोवेशन के बारे में जानकारी साझा करने की प्रदर्शनी

बीएनई

देहरादून। भारत में सरफेस इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक NITCO ने कासा ईटर्ना 2025 की मेज़बानी की। यह एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है जिसे खास तौर पर बिज़नेस पार्टनर्स और प्रोजेक्ट ऐसोसिएट्स के लिए बनाया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि गहन ज्ञान का आदान-प्रदान किया जाए जिससे NITCO की कारीगरी, टेक्नोलॉजी और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं के बारे में अंदर की जानकारी मिले। NITCO की मार्बल विशेषज्ञता के बारे में गहरा ज्ञान कासा ईटर्ना की शुरुआत सिलवासा में NITCO की अत्याधुनिक मार्बल प्रोसेसिंग फ़ैसिलिटी के गाइडेड टूर से हुई, जहाँ मेहमानों ने ये चीज़ें देखीं : भारत की पूरी तरह से स्वचालित ब्रेटन प्रोसेसिंग लाइन – ऐसी दुनिया में सिर्फ पाँच ही हैं। NITCO की 12-स्टेज ट्रिपल रीइन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी (टीआरटी) का लाइव डेमोंस्ट्रेशन प्रीमियम स्लैब, अनोखे पत्थर और नए मार्बल का चुना हुआ कलेक्शन इस दौरे से आगंतुकों को यह समझने में मदद मिली कि टेक्नोलॉजी, मैटीरियल साइंस और प्रिसिज़न प्रोसेस कैसे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और लाइफ को बेहतर बनाते हैं। डिज़ाइन इंटेलिजेंस: मोज़ेक और नेचुरा कलेक्शन मुख्य शोकेस में 50 से ज़्यादा हाथ से बने मोज़ेक पैनल दिखाए गए, जिनमें रंग, पैटर्न, डिटेलिंग और ऐडवांस्ड प्रोडक्शन टेक्नीक दिखाई गई थीं – ये सभी NITCO की सिलवासा स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाए गए थे, जिससे मोज़ेक डिज़ाइन में ब्रांड की लीडरशिप और मज़बूत हुई है। नया नेचुरा कलेक्शन भी पेश किया गया, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं : कुदरती चट्टानों से प्रेरित सरफेस सॉफ्ट-होन्ड और मैट टेक्सचर 3डी-इफ़ेक्ट डिज़ाइन सोफिस्टिकेटेड मार्बल से प्रेरित लुक हर प्रोडक्ट को प्राकृतिक ख़ूबसूरती के साथ टिकाऊपन को मिलाकर बनाया गया है, जो आज के भारतीय आर्किटेक्चर के मुताबिक है। सीखने और तकनीकी जानकारी के लिए प्लैटफ़ॉर्म कासा ईटर्ना ने तकनीकी शिक्षा और जानकारी साझा करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। प्लांट टूर, डेमोंस्ट्रेशन और डिज़ाइन सेशन के ज़रिए, उपस्थित लोगों को प्रोसेस, रीइन्फोर्समेंट, फिनिश और सरफेस की लाइफ और परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों की गहरी समझ मिली। NITCO के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक तलवार ने कहा, ''कासा ईटर्ना को हमारे पार्टनर्स को NITCO के हर प्रोडक्ट के पीछे की कारीगरी और टेक्नोलॉजी की गहरी समझ देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अपने प्रोसेस शेयर करके और अपने कलेक्शन को बढ़ाकर, हमारा मकसद भारतीय सरफेस इंडस्ट्री में क्वालिटी व डिज़ाइन के लिए नए मानक स्थापित करना है।"

अफगानिस्तान ने भारत को अपने निष्क्रिय खदान ऑफर किए

एजेंसी

नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने आर्थिक सहयोग को गहरा करने और स्थानीय रोज़गार बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत को अपने लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खदनों पर माइनिंग का ऑफर दिया है। भारतीय उद्योग संगठन एसोसिएटेड चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचौम ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। संस्था का कहना है कि खनन क्षेत्र श्थोड़ा अधिक कठिनश है और किसी भी निवेश से पहले विस्तृत भू-वैज्ञानिक तैयारी जरूरी है। एसोचौम के सेक्रेटरी जनरल मनीष सिंघल ने एक उच्चस्तरीय अफगान शिष्टमंडल से बैठक के बाद मीडिया से कहा कि अफगानिस्तान में श्कई खानें हैं जिनकी दशकों पहले पड़ताल की गई थी, लेकिन वे अब संचालित नहीं हैं। अफगान पक्ष भारतीय भागीदारी के लिए खुला है और उसने संकेत दिया कि "वे भारतीय माइनिंग कंपनियों को ये खानें ऑफर करने के लिए तैयार हैं।

भारत-इस्राइल के बीच एफटीए वार्ता फिर शुरू हुई, GTRI ने कहा- व्यापार नहीं, रणनीतिक साझेदारी है मुख्य लाभ

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत-इस्राइल के बीच चल रहे एफटीए वार्ता का सबसे बड़ा फायदा माल-व्यापार को नहीं, बल्कि दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने अपने रिपोर्ट में यह दावा किया है। दोनों देशों के बाजार में है सीमित मांग जीटीआरआई के मुताबिक, दोनों देशों के बाजार छोटे हैं और उनकी मांग भी सीमित है। इसलिए अगर एफटीए पूरा हो भी जाता है, तो सामानों के व्यापार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों देशों के लिए यह समझौता असल में रणनीतिक

सहयोग बढ़ाने का मौका है। FTA के बाद भी सामानों के व्यापार में तेज बढ़ोतरी होना मुश्किल है। इस्राइल, एक उच्च आय और प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था है। इसकी जनसंख्या 10 मिलियन से भी कम है। यह देश भारत के कपड़ा, ऑटोमोबाइल और सामान्य इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए सीमित संभावनाएं प्रदान करता है। जीटीआरआई का कहना है कि कृषि, जेनेरिक दवाइयां, इस्पात और रसायन जैसे क्षेत्रों में भारत प्रतिस्पर्धी है, लेकिन इस्राइल या तो आत्मनिर्भर है, सख्त गुणवत्ता और पादप स्वच्छता मानकों का पालन करता है, या पहले से ही यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे प्रमुख साझेदारों को टैरिफ वरीयता प्रदान करता है, जिससे भारतीय निर्यातक नुकसान में हैं। परिणामस्वरूप, द्विपक्षीय व्यापार हीरे, चावल और सिरेमिक टाइलों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ही निर्भर है। भारत-इस्राइल के आर्थिक संबंधों को गहरे करने के नए प्रयास भारत ने इस्राइल के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए एक नए प्रयास की शुरुआत की है।

89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने दुनिया को कहा अलविदा

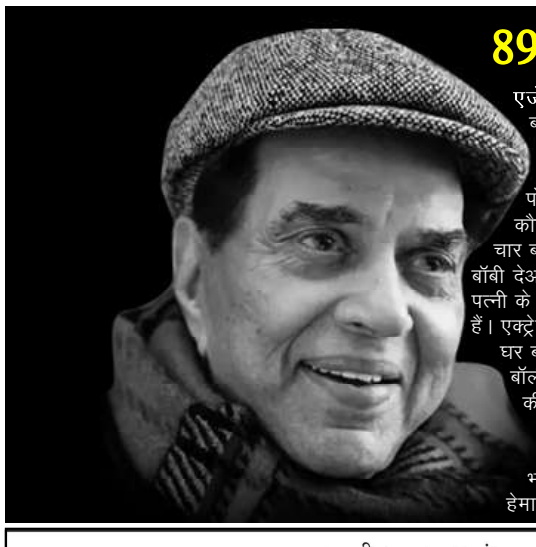

एजेंसी

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र के निधन से देओल परिवार समेत पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उम्र संबंधी बीमारियों के चलते धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद घर पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब उनके निधन की खबर सामने आई है। प्रोड्यूसर करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने 1954 में प्रकाश कौर के साथ पहली शादी की थी। तब धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत नहीं की थी। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 2 बेटे और 2 बेटियां हुईं। यानी वह चार बच्चों के पिता बन गए। एक्टर धर्मेंद्र के इन चारों बच्चों के नाम सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल है। सनी देओल और बॉबी देओल बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं। उनकी दोनों बहनें विजेता देओल और अजीता देओल लाइमलाइट से दूर रहती हैं। धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी के बच्चे सेटल हैं। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से तलाक लिए बिना 1980 में अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। हेमा मालिनी उनसे 13 साल छोटी हैं। एक्ट्रेस के साथ सात फेरे लेने के बाद कपल की दो बेटियां हुईं। इन दोनों के नाम एशा देओल और अहाना देओल है। धर्मेंद्र के बच्चों ने अपना-अपना घर बसा लिया है। सबसे बड़े बेटे सनी देओल की पत्नी पूजा हैं। वह लाइमलाइट से दूर हैं। दोनों से दो बेटे करण और राजवीर हैं। उम्मीद है कि वह बॉलीवुड में अपने करियर की जल्द शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र के दूसरे बेटे बॉबी देओल हैं। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त तान्या आहूजा के साथ शादी की है। उनके दो बच्चे हैं। उनके नाम आर्यमन और धरम है। धर्मेंद्र की दो बेटियां विजेता और अजीता अक्सर फैमिली फंक्शन में नजर आती हैं। शादी के बाद से दोनों बहनें विदेश में रहती हैं। दोनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। विजेता और अजीता दोनों ही बहनों के दो-दो बच्चे हैं। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं। पहली बेटी एशा देओल हैं। उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। एक्ट्रेस ने कारोबारी भरत तख्तानी के साथ 2012 में शादी की थी। अब दोनों का तलाक हो चुका है। एशा देओल की दो बेटियां हैं राध्या और मिराया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे छोटी बेटी अहाना देओल हैं। उनकी शादी बिजनेसमैन वैभव वोहरा के साथ हुई है। उनके तीन बच्चे हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743